इन्फोग्राफिक्स (आलेख जानकारी)

ए. कार्यप्रणाली

इस अध्ययन में अनुसूचित जनजातियों/जनजातियों/आदिवासियों की आजीविका की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित छह पहलुओं को शामिल किया गया है:

- सांस्कृतिक लोकाचार, जिसके अनुसार आजीविका चलाई जाती है
- वह संसाधन आधार जिसके अंतर्गत आजीविका चलती है
- बुनियादी ढांचे और संसाधन विकास के संदर्भ में बाहरी हस्तक्षेप
- परिवारों के स्वयं के गुण
- आजीविका में अपनाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियाँ
- आजीविका संबंधी परिणाम

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 22 जिलों और 55 ब्लॉकों में 6,019 परिवारों का एक घरेलू सर्वेक्षण; इनमें से 4,745 आदिवासी हैं, 393 पीवीटीजी हैं, और बाकी 881 गैर-आदिवासी परिवार थे। आदिवासी समुदायों की टिप्पणियों और विचारों को प्राप्त करने के लिए 50 गांवों में फोकस समूह चर्चा। आदिवासी प्रश्न से निकटता से जुड़े और जानकार 28 प्रमुख आदिवासी और गैर-आदिवासी व्यक्तियों से गहन बातचीत की गई। यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में मई 2022 से जुलाई 2022 तक और छत्तीसगढ़ में मई 2022 से अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, इस रिपोर्ट की तालिकाएँ प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

बी. सांस्कृतिक लोकाचार

सांस्कृतिक प्रथाएँ, विचारधाराएँ और आकांक्षाएँ बदल रही हैं और मेरे विचार से, यह विकास की प्रक्रिया है। 40 साल पहले जैसी स्थिति थी वैसी नहीं हैं; बाहरी दुनिया के साथ संपर्क और अंतर-सांस्कृतिक शिक्षा के चलते परिवर्तन हुआ है। हालाँकि, हम इस परिवर्तन को रोकने के लिए बाहरी दुनिया के साथ अपनी बातचीत को रोक नहीं सकते हैं; ऐसा करना हमारे अस्तित्व के लिए हानिकारक होगा।

-ऐलिस लाकड़ा

बैगा और दूसरा जनजाति, जैसे गोंड, उनमें भी अंतर है। जैसे नृत्य में देखें तो हमारा जो है चार नृत्य है- बैगा प्रभु, बैगा कर्मा, बैगा फाग और घोड़ी पेठाई। और गोंड के है सैला, रीना और डंडा। कर्मा भी करते हैं गोंड, लेकिन उनका कर्मा और बैगा का कर्मा पद्धति में अंतर होता है। और अगर आप गोदना (टैटू) देखेंगे गोंड और बैगा का, वो भी अलग होगा।

-अर्जुन सिंह धुर्वे

हालाँकि आदिवासी जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यह पदानुक्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आदिवासी समुदायों के भीतर, अनुष्ठानों और प्रथाओं में कुछ पदानुक्रम और अंतर हैं।

-ऐलिस लाकड़ा

अगर आदिवासी अपने मूल्यों, विश्वदृष्टि, जीवन शैली को बदलते हैं, तो वे अब आदिवासी नहीं कहलाएंगे। पारंपरिक व्यवस्थाएं और जीवन शैली आदिवासी समाज के स्तंभ हैं और हम इन्हें कमजोर नहीं करना चाहते हैं, अन्यथा हमें या तो हिंदू धर्म या ईसाई धर्म की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

-मानक दरपट्टी

हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत करके जमीन बनाई और हमें दिया। पर अभी जो पीढ़ी है, उनका ज़मीन से लगाव ख़तम हो रहा है। युवा पीढ़ी अपने गांव से, अपनी जमीन छोड़ कर निकलते जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। अगर आने वाले समय में उनके जमीन पर दूसरे लोगों का कब्ज़ा हो जाएगा तो अगली पीढ़ी के पास जमीन नहीं रहेगी। ज़्यादातर गाँव में हमारे पास जो जमीन और संसाधन है, सरकार अगर उसमे में से ही रोज़गार का प्रावधान करे तो ही, एक आदिवासी और उनके संस्कृति का अस्तित्व बच सकता है , साथ में युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं जो गांव से पलायन कर रहे हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) मिलने चाहिए ताकि उनकी संस्कृति बचे रहे।

-ममता कुंजूर

मुझे लगता है कि आदिवासियों को गैर-आदिवासियों से जो एक चीज़ सीखनी चाहिए वह है थोड़ा अधिक व्यवसायिक मानसिकता वाला होना। आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं हैं, उनके पास जो कुछ भी है उससे वे खुश हैं।

-गोदावरी मरावी

आदिवासी समाज को टोटेम सिस्टम में बांटा गया है और ज्यादातर मामलों में ये टोटेम स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां हैं। एक विशेष कुलदेवता के लोग अपने कुलदेवता की रक्षा करते हैं और यदि किसी क्षेत्र में 750 कुलदेवता हैं, तो 750 प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। इसलिए, प्राकृतिक विविधता की रक्षा करना उनके सिस्टम में शामिल है।

-अश्विनी कांगे

आदिवासी धन का संचय नहीं करते है। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं। आदिवासियों में उच्च स्तर का आत्म-सम्मान होता है, वे कभी भीख नहीं मांगते।

-संपतिया उइके

आदिवासी भविष्य के बारे में नहीं सोचते/परवाह नहीं करते, वे केवल आज के भोजन के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर, गैर-आदिवासी भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसकी परवाह करते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवसाय करते हैं। गैर-आदिवासी समुदाय के बच्चे बचपन से ही अपना काम-धंधा शुरू कर देते हैं लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते। हमें भी ऐसा ही करना सीखना चाहिए ताकि हम भी कल (भविष्य) के लिए तैयारी कर सकें।

-अनुसुइया मरावी

सी. सरकारी और गैर-सरकारी हस्तक्षेप

अगर हम सीएफआर की बात करें, तो उसका सपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए ताकि आदिवासी सीएफआर में दिए गए प्रबंधन को अपने हाथों में ले सकें। पेसा के क्रियान्वयन गांव स्तर में जाने की जरूरत है तकी हर एक व्यक्ति को इसका पता चले।

-लता नेताम

एफ आर ए (FRA) को लागू करने की जिम्मेदारी आदिवासी विभाग को दी गई थी और जिम्मेदार अधिकांश कर्मचारियों को संदर्भ के साथ-साथ अधिनियम के बारे में कोई स्पष्ट समझ नहीं है। यदि अधिनियम को उसकी वास्तविक भावना में लागू करना है, तो कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार लोगों को नेक इरादे और उचित रूपरेखा की आवश्यकता होगी।

-बलवंत रहांगडाले

सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासियों और पीवीटीजी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हालाँकि, कई मामलों में इससे उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, पुराने मिट्टी के घरों को कंक्रीट संरचनाओं से बदला जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही उनकी जरूरत और मौसम के अनुकूल घर कैसे बनाएं, इसकी जानकारी भी अनावश्यक होती जा रही है। घास,लंबी पत्तियों को उगाने और उससे संसाधित करने का ज्ञान जो उन पारंपरिक घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वह लुप्त हो रहा है। यदि इन योजनाओं का तैयार प्रारूप करते समय पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखा जाए तो यह मददगार होगा। इस उदाहरण में पारंपरिक सामग्री और तरीकों का उपयोग करके घरों को बेहतर बनाने में कंक्रीट के घरों की तुलना में कम लागत आएगी।

-एतवारी मचिया बैगा

आदिवासी समुदायों के अपने रीति-रिवाज हैं और उन्हें 'पेसा' के माध्यम से मान्यता दी गई है। इस अधिनियम में बहुत स्पष्ट रूप से प्रथागत कानूनों का सम्मान करने और उन्हें स्वीकार करने के बारे में कहा गया है। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों की ताकत बन सकता है तथा उनकी पहचान बाकी मुख्य-धारा के समाज से अलग दर्शा सकता है।

-ऐलिस लाकरा

पीएम आवास योजना भी आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रही है। पहले कई बार पुरुष दूसरी महिलाओं से शादी करने के लिए अपनी पत्नियों को छोड़ देते थे। परित्यक्त महिलाओं को अपना ससुराल छोड़ना पड़ता था। अब पीएम आवास के तहत बनने वाले घर महिलाओं के नाम पर है। इससे महिलाओं को मदद मिली है क्योंकि उन्हें उनके घरों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।

-संपतिया उइके

एफआरए से एक अच्छी शुरुआत हुई है, हालाँकि और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। वन आधारित आजीविका में सुधार एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार और सीएसओ, दोनों को काम करने की जरूरत है ताकि उन्हें वन उपज का अधिक मूल्य मिल सके। बाज़ार तक पहुँच अभी भी एक मुद्दा है और मूल्यवर्धन से बाज़ार से जुड़ने में मदद मिल सकती है।

-पल्लवी जैन गोविल

एसएचजी ने बचत करने, ऋण लेने और व्यवसाय करने के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की है।

-संपतिया उइके

लोगों के लिए कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले हमें उन लोगों की सांस्कृतिक विरासत को समझने की ज़रूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा दृष्टिकोण और विचार उनकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं से मेल न खाएं। और इसी विसंगति के कारण कई योजनाएं और परियोजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जरूरी नहीं कि समुदाय उन्हें दी गई प्रत्येक चीज़ को स्वीकार करेगा, अतः कार्यक्रम नियोजकों और नीति-निर्माताओं को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

-सैबल जाना

छत्तीसगढ़ में सरकार ने यह माना है कि किसी भी समुदाय के विकास में भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए, सरकार ने स्थानीय बोली और भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यमों में से एक के रूप में शामिल किया। उदाहरण के लिए, बस्तर में बच्चों को हल्बी या गोंडी भाषा में पढ़ाया जा रहा है।

-ऐलिस लाकरा

सड़क से संपर्क

गांव बारहमासी सड़कों द्वारा ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं

मध्य प्रदेश

आदिवासी	78%
सड़कें अच्छी स्थिति में	62%
गैर-आदिवासी	79%
सड़कें अच्छी स्थिति में	54%
पीवीटीजी	80%
सड़कें अच्छी स्थिति में	64%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	80%
सड़कें अच्छी स्थिति में	78%
गैर-आदिवासी	100%
सड़कें अच्छी स्थिति में	88%
पीवीटीजी	82%
सड़कें अच्छी स्थिति में	64%

SAL 2021 से पता चलता है

गांव बारहमासी सड़कों द्वारा ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं

ओडिशा

आदिवासी	72%
सड़कें अच्छी स्थिति में	47%

झारखंड

आदिवासी	74%
सड़कें अच्छी स्थिति में	58%

वर्ष 2020 में मिशन अंत्योदय, भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय औसत **68%** है[1]

[1]https://missionantyodaya.nic.in/ma2020/preloginStateFacilityReports2020.html

सार्वजनिक परिवहन

मध्य प्रदेश

आदिवासी	42%
गैर-आदिवासी	63%
पीवीटीजी	80%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	30%
गैर-आदिवासी	40%
पीवीटीजी	9%

गांव सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से अपने ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	46%

झारखंड

आदिवासी	57%

मिशन अंत्योदय, भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार
वर्ष 2020 में राष्ट्रीय औसत 69.11% है

मोबाइल नेटवर्क

मध्य प्रदेश

आदिवासी	66%
गैर-आदिवासी	84%
पीवीटीजी	90%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	72%
गैर-आदिवासी	100%
पीवीटीजी	64%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	74%

झारखंड

आदिवासी	73%

गांव कम से कम एक मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर किए गए हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की 31 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के आंकड़ों से पता चला कि मार्च 2022 तक, **भारत के 6,44,131 गांवों में से 5,98,951 गांव (लगभग 93%) मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर किए गए हैं।**

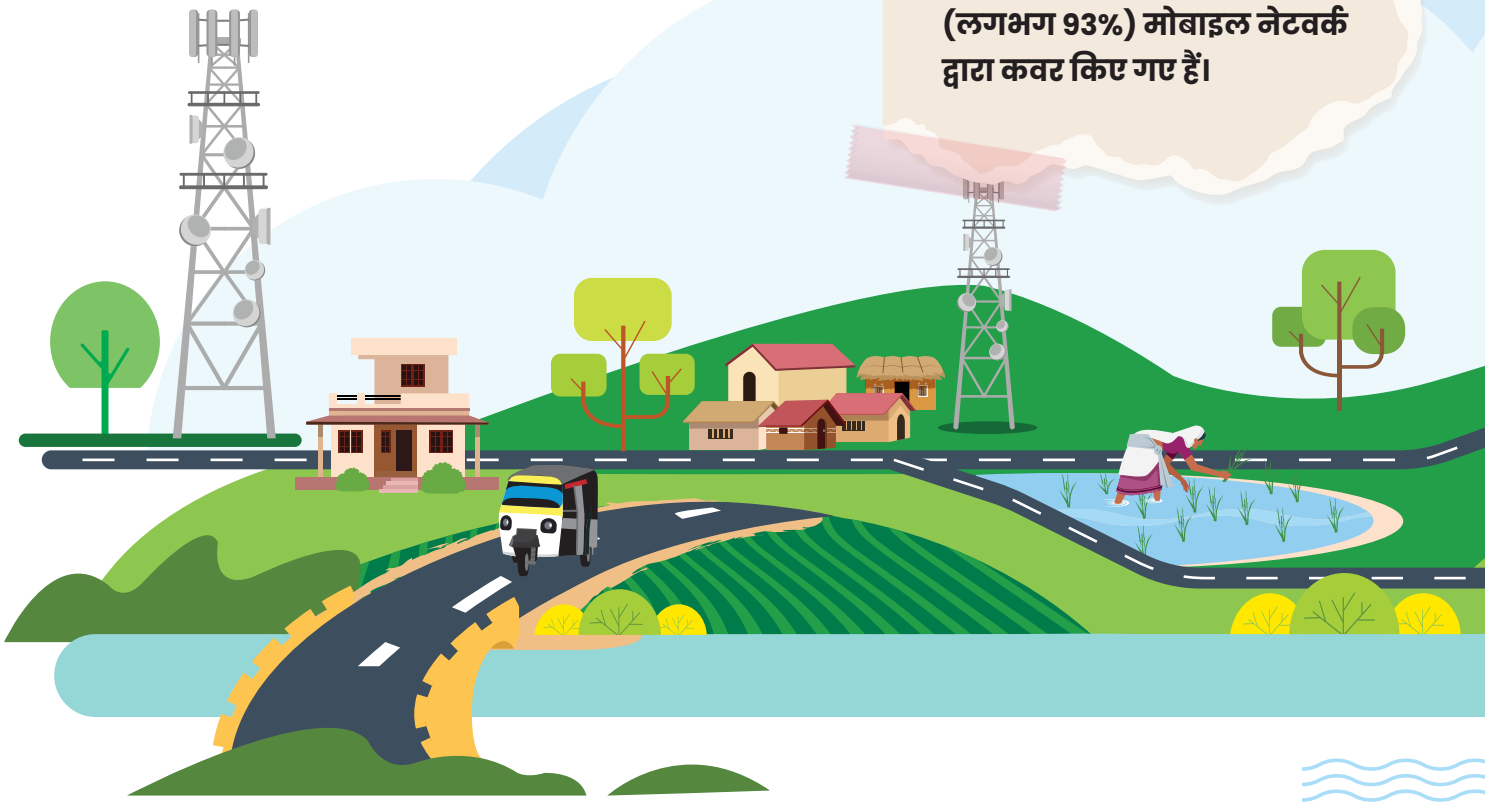

स्मार्टफोन का स्वामित्व

मध्य प्रदेश

आदिवासी परिवार
18% 7%

गैर-आदिवासी परिवार
45% 27%

पीवीटीजी परिवार
15% 4%

छत्तीसगढ़

आदिवासी परिवार
20% 11%

गैर-आदिवासी परिवार
42% 29%

पीवीटीजी परिवार
7% 3%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी परिवार
6% 5%

झारखंड

आदिवासी परिवार
21% 9%

न्यूज़ू की ग्लोबल मोबाइल मार्केट रिपोर्ट[2] के अनुसार, **भारत में 659 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, जो आबादी का लगभग 46.5% है।**

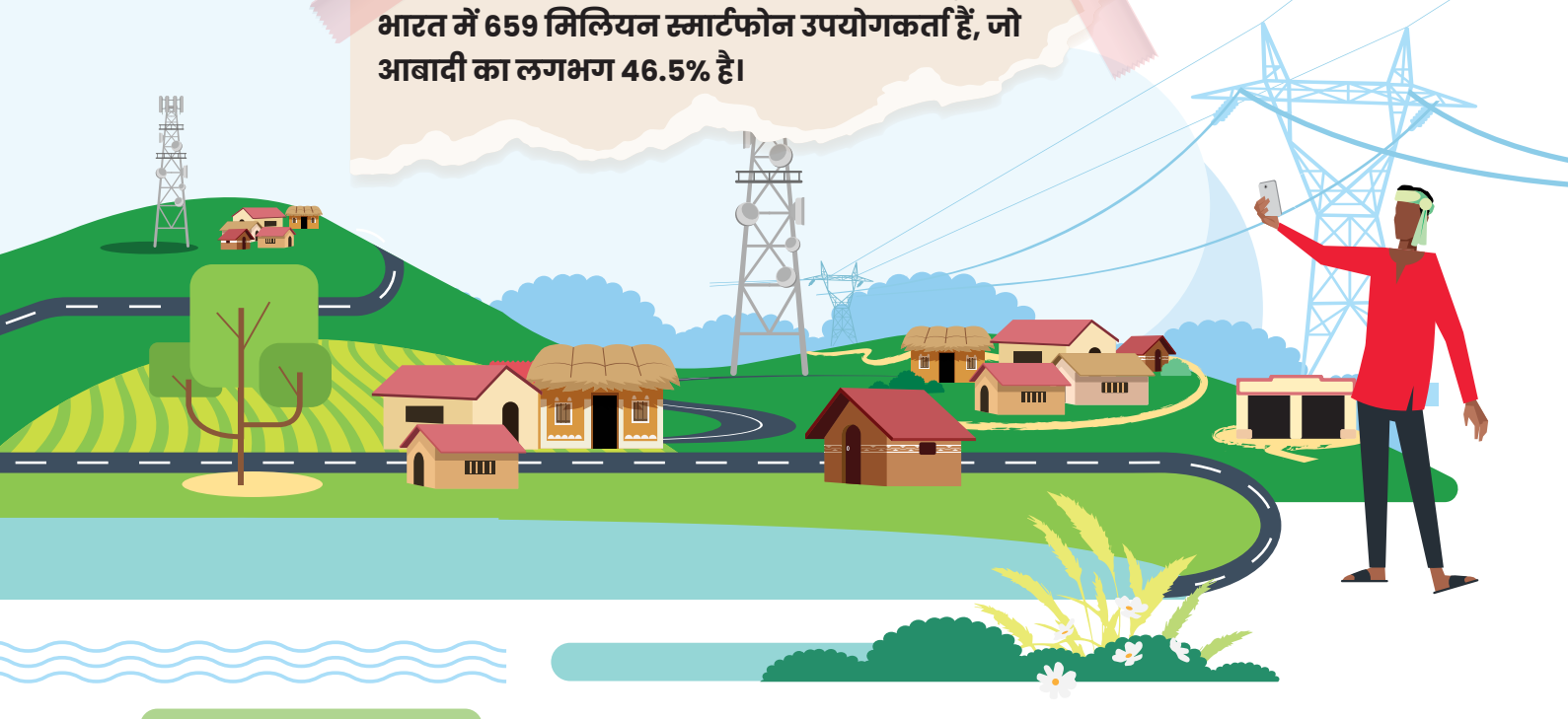

[2]https://newzoo.com/resources/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users

गांवों में

आंगनवाड़ी

मध्य प्रदेश

आदिवासी	98%
गैर-आदिवासी	95%
पीवीटीजी	100%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	100%
गैर-आदिवासी	100%
पीवीटीजी	100%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	89%

झारखंड

आदिवासी	84%

गांवों में एक आंगनवाड़ी केंद्र है।

वर्ष 2020 में भारत सरकार के मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण में बताया गया है कि **भारत के 79% गांवों में आंगनवाड़ी है।**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

मध्य प्रदेश

आदिवासी	51%
गैर-आदिवासी	63%
पीवीटीजी	50%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	63%
गैर-आदिवासी	88%
पीवीटीजी	36%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	31%

झारखंड

आदिवासी	58%

गांवों में पीडीएस आउटलेट है।

वर्ष 2020 में मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण से पता चलता है कि **भारत के 48.27% गांवों में पीडीएस आउटलेट है।**

डी. परिवार की विशेषताएं

सरकार ने अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास सुविधाओं के साथ प्राथमिक और आवासीय विद्यालय स्थापित करने में काफी अच्छा काम किया है। इससे पता चलता है कि आदिवासी स्कूलों के नतीजे अन्य पब्लिक स्कूलों की तुलना में अच्छे या उससे भी बेहतर हैं। इसलिए आदिवासियों को अच्छी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के मामले में, हमने (सरकार ने) कुछ इलाकों को छोड़कर, जहां स्कूल छोड़ने की दर अभी भी बहुत अधिक है, काफी अच्छा काम किया है।

-पल्लवी जैन गोविल

गैर-आदिवासी हमारे साथ भेदभाव करते हैं क्योंकि हमारी जीवनशैली, पहनावा अलग है, हम आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अगर किसी बैंक में जाएं और कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, तो कभी-कभी गैर-आदिवासी कहेंगे, "हटो जरा तुम और बड़े लोग आगे चले जाएंगे।" जिनके पास अधिक संपत्ति होती है उनका समाज में ऊंचा स्थान होता है।

-अनुसुइया मरावी

अन्य क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में बाजार के साथ संबंध धीरे-धीरे बदल रहे हैं। हालाँकि, बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा गेम चेंजर साबित होगी। जब वे सीबीएसई डिप्लोमा या कॉलेज डिप्लोमा पूरा करके अच्छे के विश्वास के साथ एक शैक्षणिक संस्थान से निकालेंगे, तो वे बाजार में अपना काम बेहतर ढंग से करने में सक्षम होंगे।

-पल्लवी जैन गोविल

यदि हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों, अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान और अधिकारों के बारे में जाने, तो स्कूलों में ग्राम सभा, पेसा, कृषि, वन, प्रकृति, कलात्मकता आदि के बारे में उनके ज्ञान के बारे में पढ़ाने की आवश्यकता है।

-गंगाराम पैकरा

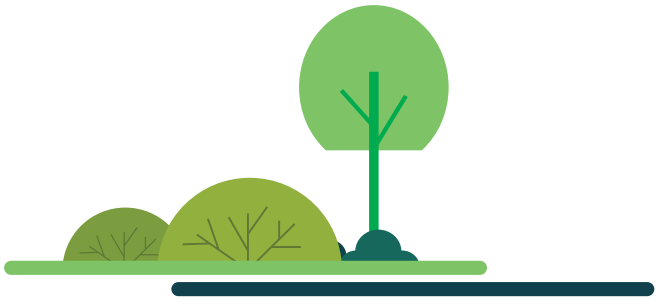

साक्षरता

मध्य प्रदेश

पीवीटीजी परिवार	83%
आदिवासी परिवार	75%

परिवारों का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक स्तर से आगे शिक्षित नहीं है, और उनमें से अधिकांश की कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में ये अनुपात:

छत्तीसगढ़

पीवीटीजी परिवार	87%
आदिवासी परिवार	66%

मध्य प्रदेश में परिवार के मुखिया की शिक्षा प्राप्ति

शिक्षा का स्तर (कुल का%)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्कूली शिक्षा नहीं	58.3	31.3	69
प्राथमिक से कम	8.8	4.9	4
प्राथमिक	9.3	18.6	9.5
मैट्रिक से कम और प्राइमरी से ज़्यादा	15.2	28.4	13.5
मैट्रिकुलेशन और उससे ऊपर	8.4	16.8	4

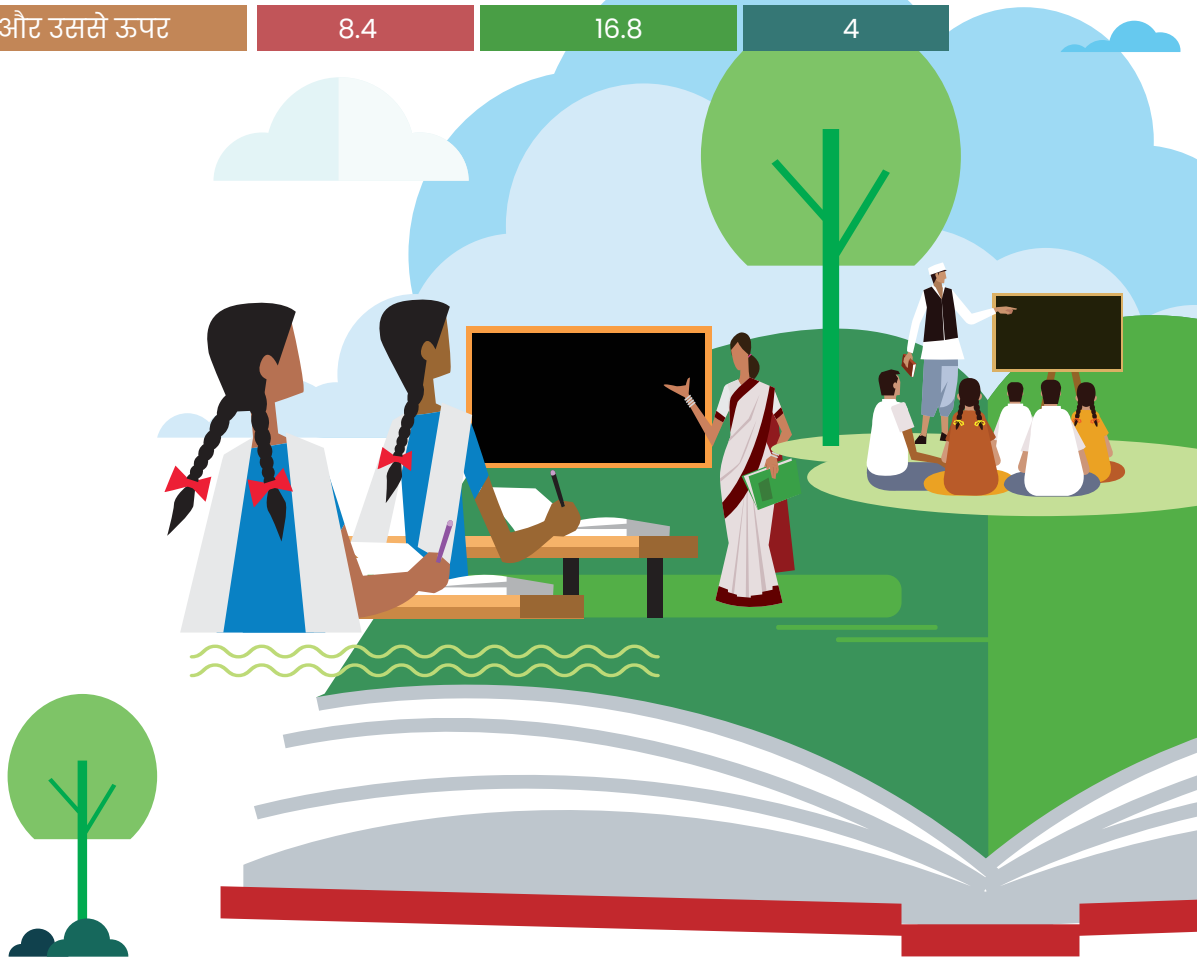

छत्तीसगढ़ में परिवार के मुखिया की शिक्षा प्राप्ति

शिक्षा का स्तर (कुल का%)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्कूली शिक्षा नहीं	49	38.2	65.6
प्राथमिक से कम	6.8	9.5	12
प्राथमिक	11.5	12.2	12
मैट्रिक से कम और प्राइमरी से ज़्यादा	20.3	24.9	8.3
मैट्रिकुलेशन और उससे ऊपर	12.4	15.2	2.1

SAL 2021 से पता चलता है

झारखंड

आदिवासी परिवार	82%
गैर-आदिवासी परिवार	72%

के मुखिया मैट्रिक से कम पढ़े हैं

ओडिशा

आदिवासी परिवार	87%
गैर-आदिवासी परिवार	82%
पीवीटीजी परिवार	90%

के मुखिया मैट्रिक से कम पढ़े हैं

राष्ट्रीय औसत: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के बारे में एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट (जुलाई 2017 - जून 2018) के **अनुसार साक्षरता दर लगभग 77.7% थी, जिसमें पुरुषों के लिए 84.7% और महिलाओं के लिए 70.3% थी। यही रिपोर्ट शहरी क्षेत्रों में 87.7% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 73.5% दर्शाती है।**

जमीन की जोत

मध्य प्रदेश

आदिवासी	36%
गैर-आदिवासी	43%
पीवीटीजी	36%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	5%
गैर-आदिवासी	32%
पीवीटीजी	48.4%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	15%
गैर-आदिवासी	28%
पीवीटीजी	47%

झारखंड

आदिवासी	12%
गैर-आदिवासी	30%

परिवार भूमिहीन हैं।

राष्ट्रीय औसत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587 -77/33.1/1 से पता चलता है कि **8.2% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं**।

मध्य प्रदेश

भूमिधारिता श्रेणी	आदिवासी		गैर-आदिवासी		पीवीटीजी	
	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार
भूमिहीन	36.1	40.6	42.8	42.5	36.4	25.8
सीमांत	38.3	39.5	32.4	34.8	36.3	54.5
छोटी	12.9	10.8	12.7	10.6	12.4	7.6
छोटी-मध्यम	11.4	8.1	9.1	4.5	10.9	10.6
मध्यम	0.9	0.5	1.9	1.5	3.5	1.5
बड़ी	0.4	0.5	1.1	6.1	0.5	0.0

छत्तीसगढ़

भूमिधारिता श्रेणी	आदिवासी		गैर-आदिवासी		पीवीटीजी	
	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार
भूमिहीन	15.2	23.0	32.1	49.6	48.4	57.8
सीमांत	51.8	53.3	48.3	40.9	34.4	24.4
छोटी	18.8	13.5	12.7	8.7	8.3	11.1
छोटी-मध्यम	12.4	9.0	6.5	0.9	6.8	4.4
मध्यम	1.3	0.7	0.4	0.0	2.1	2.2
बड़ी	0.5	0.5	0	0.0	0	0.0

औसत भूमि जोत

मध्य प्रदेश

आदिवासी 3.9 एकड़

पीवीटीजी 4.4 एकड़

छत्तीसगढ़

आदिवासी 3.2 एकड़

पीवीटीजी 3.0 एकड़

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी 1.9 एकड़

पीवीटीजी 1.3 एकड़

झारखंड

आदिवासी 2.3 एकड़

राष्ट्रीय औसत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587 -77/33.1/1 से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार के स्वामित्व वाला औसत क्षेत्र **0.876 हेक्टेयर है**।

सिंचाई

मध्य प्रदेश में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्वयं की भूमि (प्रतिशत)	17.5	28.0	30.2
भूमि पट्टे पर (प्रतिशत)	20.2	28.6	36.8
भूमि में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	21.9	16.7	46.2

छत्तीसगढ़ में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्वयं की भूमि (प्रतिशत)	12.4	17.2	2.0
भूमि पट्टे पर (प्रतिशत)	6.0	26.7	0.0
भूमि में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	10.1	12.5	0.0

झारखंड में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

आदिवासी परिवार	18.5%
गैर-आदिवासी परिवार	16.4%

ओडिशा में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

आदिवासी परिवार	7.4%
गैर-आदिवासी परिवार	12.4%
पीवीटीजी परिवार	42.9%

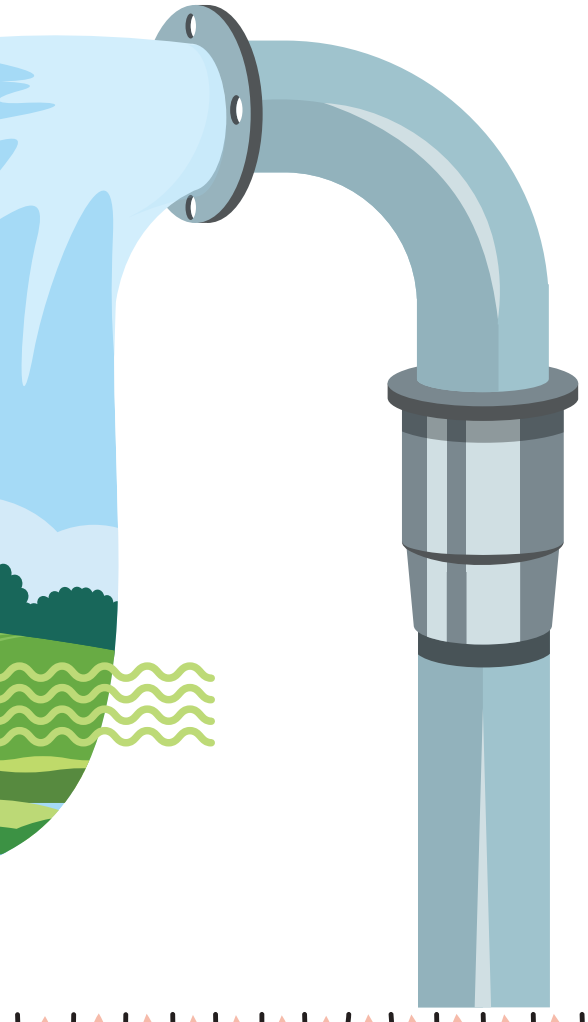

ओडिशा

आदिवासी	7.4%
गैर-आदिवासी	12.4%
पीवीटीजी	42.9%

झारखंड

आदिवासी	18.5%
गैर-आदिवासी	16.4%

परिवारों के पास सभी मौसमों के लिए सिंचाई की सुविधा है

वनों तक पहुंच

मध्य प्रदेश

आदिवासी	62%
पीवीटीजी	98%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	90%
पीवीटीजी	98%

ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता बताई।

वन दूरी (मध्य प्रदेश)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की जंगल से औसत दूरी (किमी)	2.0	3.2	1.8
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	62	40	98
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों के लिए जंगल से औसत दूरी (किमी)	6.8	9.2	0.2
वे परिवार जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	38	60	2

वन दूरी (छत्तीसगढ़)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की जंगल से औसत दूरी (किमी)	1.8	2.1	0.3
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	90	64	98
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों के लिए जंगल से औसत दूरी (किमी)	2.6	9.4	0.3
वे परिवार जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	10	36	2

आदिवासी 75%

आदिवासी 53%

परिवार जंगल पर निर्भर हैं।

ई. आजीविका संबंधी गतिविधियाँ

पहले हम कुटकी, मरुआ, अरहर जैसे जितने भी पानी या कम पानी की जरुरत वाला फसल लेते थे। इसके अलावा वन से फल, फूल, कांदा, साग, भाजी मिल जाता था। फिर बाहरी लोगों का आगमन, व्यवसायों का आगमन से धीरे-धीरे फसल का स्थिति बदलना शुरु हुआ। फिर वो सीखने लग गए की आधुनिक खाद डालो इसे तुम्हारा उत्पादन अच्छा होगा, तो हम लोगों ने उपयोग और इससे बनाना भी शुरु किया।

-शेर सिंह अचला

जंगल के सामान को जब सिर्फ पैसे से तौला जाता है तो बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। बाज़ार से लोगो के पास डिमांड आती है कि हमें इतना सामान चाहिए और इतना पैसा मिलेगा। इस चक्कर में लोग पूरा का पूरा पेड़ काट डालते हैं और एक साल काट देते हैं तो दूसरा साल फिर कहां मिलेगा? ऐसे करके अब भी बहुत सारा पेड़ पौधा जैसे चार, चिरौंजी, हर्रा, बांस ये सब खत्म हो गया।

-अर्जुन सिंह धुर्वे

बैगा जंगल से विभिन्न मौसमों में लगभग 43 प्रकार की साग-सब्जियाँ, 15 से अधिक प्रकार की जड़ें, 20 से अधिक प्रकार के फल इकट्ठा करते थे। ये विभिन्न मौसमों में उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता को सुनिश्चित करते थे।

-बलवंत रहांगडाले

पहले लोगों को जंगल से विभिन्न प्रकार का भोजन मिलता था जो बहुत पौष्टिक होता था और बीमारियों को रोकने में मदद करता था। उदाहरण के तौर पर, पहले आदिवासियों में मधुमेह का रोगी नहीं पाया जाता था। हम कोडो, कुटकी, मक्का खाते थे। इन्हें बिना किसी रासायनिक इनपुट के उगाया जाता था। धीरे-धीरे चावल और गेहूं का प्रचलन शुरु हुआ और ये आदिवासियों के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं थे। आदिवासियों ने चावल और गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए रासायनिक खेती भी करना शुरु कर दिया। इससे उनकी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

-संपतिया उइके

पलायन को कम करने और आदिवासी युवाओं को अपनी संस्कृति और कृषि में रुचि लेने के लिए गांवों में आजीविका के अवसर पैदा करना महत्वपूर्ण है।

- लता उसेंडी

छत्तीसगढ़ के मामले में अगर आप देखेंगे कि सक्रिय राजनीति में कौन-कौन हैं, तो वहां गोंड या उरांव या कंवर जैसे समुदाय होंगे। इसी तरह उरांव सरकारी नौकरी में भी हैं। आप शायद ही किसी पंडो या मांझी या मझवार को इन आजीविका विकल्पों को चुनते हुए पाएंगे। वे ज्यादातर कृषि या मजदूरी पर निर्भर होते है। बैगा और पहाड़ी कोरवा कुछ अन्य जनजातियों की अपेक्षा वनों पर अधिक निर्भर रहते है।

-गंगाराम पैकरा

आजकल लोग कम पलायन कर रहे हैं। वे गांव में ही मनरेगा के तहत 100 दिनों तक मजदूरी का काम पा सकते हैं।

-गोदावरी मरावी

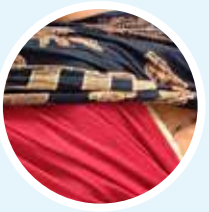

यह अच्छी बात है कि हममें से कुछ लोगों की पहचान शहरी अभिजात वर्ग में की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक ग्रामीण युवा कौशल को कैसे अपना सकते हैं।

-भूरी बाई

कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान, मध्य प्रदेश क्षेत्रवार

	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
आय का स्रोत	बी	जी	अन्य	कुल	बी	जी	अन्य	कुल	बी	जी	अन्य	कुल
खेती	60	33	26	44	62	57	44	53	#N/A	16	53	36
पशुपालन	-3	-4	-3	-3	-1	-4	-4	-3	#N/A	-1	-2	-2
वनोपज	0	4	4	2	0	2	1	1	#N/A	6	7	6
मजदूरी	28	35	57	37	27	22	45	32	#N/A	43	29	35
गैर-कृषि उद्यम	2	1	3	2	5	6	3	4	#N/A	0	0	0
प्रेषण	6	8	6	7	2	5	4	4	#N/A	4	9	7
वेतन और पेंशन	7	23	8	12	5	12	8	9	#N/A	31	4	17

बी= भील क्षेत्र, जी= गोंड क्षेत्र, अन्य = अन्य आईटीडीपी ब्लॉक, कुल= मध्यप्रदेश कुल

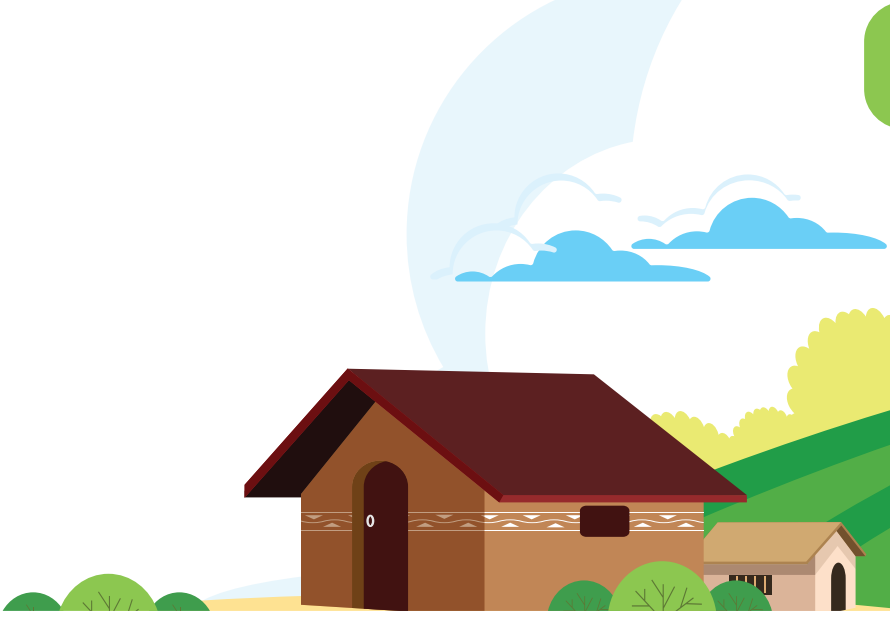

कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान, छत्तीसगढ़ क्षेत्रवार

	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
आय का स्रोत	द	मध्य	उत्तर	कुल	द	मध्य	उत्तर	कुल	द	मध्य	उत्तर	कुल
खेती	56	37	59	51	46	34	57	45	41	27	24	33
पशुपालन	-2	-8	-3	-4	-1	-3	-2	-2	1	0	-1	0
वनोपज	6	13	4	8	6	1	1	3	4	15	30	14
मजदूरी	24	53	25	34	32	63	29	41	6	44	39	26
गैर-कृषि उद्यम	1	0	2	1	1	-1	1	0	0	1	0	0
प्रेषण	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
वेतन और पेंशन	14	3	11	9	14	5	13	11	48	13	8	28

द= दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य = मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर = उत्तर छत्तीसगढ़, कुल = छत्तीसगढ़ कुल

एफ. आजीविका संबंधी परिणाम

बाजार बहुत बदल गया है। पहले बाजार लोकल तक ही सीमित था, न सड़क न वेब नेटवर्क था। जो कुछ भी उत्पादित होता था, उस में शायद ही कुछ बचा हुआ करता था और उनमें से अधिकांश का स्थानीय स्तर पर उपभोग किया जाता था। जरूरत का एहसास भी कम था। अब हम दुनिया से जुड़ गए हैं, बस्तर के वन और कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकते हैं। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को भी कई तरह से बाजार ने आकार दिया है। चिप्स और मैगी जैसी चीजें हर स्थानीय बाजार में उपलब्ध हैं।

-अरविन्द नेताम

क्या है कि मार्केटिंग अभी भी कोरोना काल से थोड़ा सा डाउन हो गया है। जो ऑर्डर-वोर्डर आते थे अपने पास में वो नहीं आ पा रहे हैं। और एग्जिबिशन वगैरा, मेला वेला लगते थे बहुत सारी जगह तो वो सारी चीजें नहीं हो पा रहा है।

-विजय धुर्वे

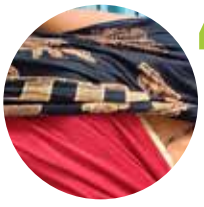

बच्चे अब कोदो कुटकी खाना पसंद नहीं करते। पी डी एस (PDS) में भी धान का वितरण किया जाता है। चावल बनाने में कम समय और मेहनत लगती है इसलिए महिलाओं के लिए इसे बनाना आसान होता है। चावल-मिल आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन कोदो-कुटकी को प्रोसेसिंग करने के लिए कोई मशीनीकृत सुविधा उपलब्ध नहीं है।

-गोदावरी मरावी

अधिकांश आदिवासी गांवों में लोगों को एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) का पहुंच प्राप्त है। चूंकि आईसीडीएस मध्याह्न भोजन प्रदान करता है, इसलिए बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन मिल पाता है।

-इंदिरा मंडावी

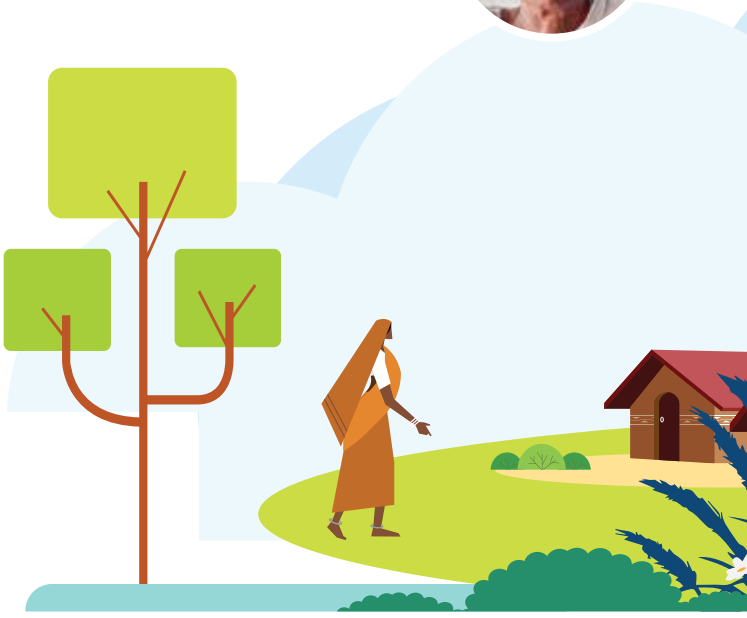

औसत वार्षिक घरेलू आय

राज्यवार

औसत वार्षिक आय :

मध्य प्रदेश

आदिवासी	रु. 73,900
गैर-आदिवासी	रु. 84,033
पीवीटीजी	रु. 68,726

छत्तीसगढ़

आदिवासी	रु. 53,610
गैर-आदिवासी	रु. 53,766
पीवीटीजी	रु. 43,012

क्षेत्र-वार

भील क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय, भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	99,211	1,45,289	
प्रति-व्यक्ति आय	24,571	36,875	
परिवारों की संख्या	820	45	0

गोंड क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय, भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	66,724	69,755	79,564
प्रति-व्यक्ति आय	15,077	13,800	20,732
परिवारों की संख्या	758	156	81

अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	52,597	80,084	61,411
प्रति-व्यक्ति आय	12,596	20,034	13,043
परिवारों की संख्या	719	134	120

दक्षिण क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	54,961	60,092	1,06,223
प्रति-व्यक्ति आय	12,137	13,944	17,366
परिवारों की संख्या	742	172	35

मध्य क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	57,072	52,980	45,468
प्रति-व्यक्ति आय	14,177	14,668	14,198
परिवारों की संख्या	708	159	57

उत्तर क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	49,599	48,033	19,488
प्रति-व्यक्ति आय	13,063	12,071	6,969
परिवारों की संख्या	861	168	100

SAL 2021 से पता चलता है -परिवारों की वार्षिक आय

ओडिशा

आदिवासी रू. 61,263

झारखंड

आदिवासी रू. 75,378

एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587 -77/33.1/1 से पता चलता है कि **वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि परिवारों की औसत वार्षिक आय रू. 122,616 है**

खाद्य सुरक्षा

मध्य प्रदेश

आदिवासी	32%
गैर-आदिवासी	27%
पीवीटीजी	61%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	27%
गैर-आदिवासी	42%
पीवीटीजी	29%

परिवार गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की सूचना देते हैं।

मध्य प्रदेश

आदिवासी	4.2%
गैर-आदिवासी	2.4%
पीवीटीजी	1.1%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	2.2%
गैर-आदिवासी	2.5%
पीवीटीजी	19%

परिवार खराब आहार विविधता वाले हैं।

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा में परिवार गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित हैं।

ओडिशा

आदिवासी	12%

झारखंड

आदिवासी	25%

यूएन-इंडिया के अनुसार, भारत में लगभग **195 मिलियन लोग कुपोषित लोग हैं, जो इसकी आबादी का लगभग 16% है**